

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2013/आषाढ़ 24, 1935 No. 154] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2013/ASADHA 24, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2013

विषय:— आस्ट्रेलिया, ईयू और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 14/01/2013/डीजीएडी.— मै. मनाली पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर (जिन्हें एतद्पष्चात सम्बद्ध देष कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (जिसे एतद्पष्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी षुल्क की जांच प्रारंभ करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पष्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष समय—समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क प्रषुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पष्चात अधिनियम कहा गया है) और समय—समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क प्रषुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी षुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पष्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार एक आवेदनपत्र दायर किया है।

और यतः, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह उपपादित करते हैं कि सम्बद्ध देषों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षित और कथित पाटन एवं 'क्षित के बीच कारणात्मक सम्बंध मौजूद है जिससे पाटनरोधी जांच प्रारंभ करना न्यायोचित ठहरता हैं; इसिलए प्राधिकारी, कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी षुल्क की ऐसी राषि की सिफारिष करने, जो यदि उद्ग्रहित की गई तो घरेलू उद्योग की 'क्षित' को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए प्राधिकारी कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित की जांच करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में दी गई षतों के अनुरूप एतद्द्वारा जांच प्रारंभ करते हैं।

3130 GI/2013 (1)

घरेलू उद्योग एवं 'आधार'

- 2. यह आवेदनपत्र घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स मनाली पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मैसर्स मनाली पेट्रोकैमिकल्स ने दावा किया है कि वे सम्बद्ध वस्तु के भारत में एकमात्र उत्पादक हैं और इसलिए नियम 2(ख) के आषय के अंतर्गत वह घरेलू उद्योग हैं तथा नियम 5(3) और उसके अंतर्गत बने नियमों में किए गए उल्लेख के अनुसार यह आवेदनपत्र आधार के मानदंड को पूरा करता है। विचाराधीन उत्पाद
- 3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सम्बद्ध देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित पलेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल, एक पालीमर है। सम्बद्ध उत्पाद 3000—4000 मालिक्यूलर बजन का एक स्पष्ट विस्कोस द्रव होता है जिसका विनिर्माण ट्रायोल चैन स्टार्टर के साथ प्रोपाइलीन आक्साइड और इथायलीन आक्साइड का पालिमराइजेषन करके किया जाता है। यह एक पालीईथर होता है और कैटालिस्ट और एडिटिब्ज के साथ प्रतिक्रिया करके पालीयूरीथीन फोम बनाता है जिसका प्रयोग अपहोल्स्टरी, चटाइयों, तिकया, बोलस्टर्स, परिवहन सीटिंग और पैकेजिंग के लिए किया जाता है। पलेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल (जिसे एतद्पष्चात "सम्बद्ध वस्तु" कहा गया है) का परिवहन आस्ट्रेलिया, ई यू और सिंगापुर से टैंकरों अथवा इस्पात के ड्रमों में भंडारण करके किया जाता है। इसे सीमाषुल्क प्रषुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक्स तथा उसकी मदों" के वर्ग के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुरूप 3907.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

समान मदें

- 4. आवेदक ने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तु जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में तकनीकी विनिदेषनों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तनकीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "समान मद" के रूप में माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देषों से आयात की जा रही सम्बद्ध वस्तु को "समान मद" के रूप में माना जा रहा है। अंतर्ग्रस्त देष
 - 5. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देष आस्ट्रेलिया, ई यू और सिंगापुर है। सामान्य मृल्य
- 6. आस्ट्रेलिया, ई यू और सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्यः आवेदक ने इन सम्बद्ध देषों के लिए सामान्य मूल्य का विनिर्माण यह उल्लेख करते हुए किया है कि वे सम्बद्ध देषों में सम्बद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा भरोसेमंद सूचना प्रदान करने में सक्षम हुए है और न ही यह सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्राधिकारी ने इस जांच षुरूआत के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विनिर्मित मूल्य के आधार पर सम्बद्ध देषों से सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है। निर्यात कीमत
- 7. आवेदक ने एक्सिमनेट बीबीएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए समुद्री भाडा, सामुद्रिक बीमा, अंतरदेषीय परिवहन, कमीषन, पत्तन पर रखरखाव और पत्तन प्रभार के अनुरूप कीमत समायोजन करने की अनुमित दी है। सम्बद्ध देषों से सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो यह पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं। पाटन मार्जिन

- 8. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना फैक्टरी बाह्य स्तर पर की गई है जो सम्बद्ध वस्तु के बारे में प्रथम दृष्टया भारी पाटन मार्जिन का निर्धारण करती है। इस बात के, प्रथमदृष्टया, पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध देषों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे, प्रथम दृष्टया, यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देषों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजारों में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन का आकलन न्यूनतम से अधिक पर किया जाता है। क्षति एवं कारणात्मक संबंध
- 9. आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ती मात्रा के रूप में कथित पाटन कीमत अधोरदन, कीमत अधोक्रियण, कीमत निग्रहण और लाभप्रदायकता, लगाई गई पूंजी पर अर्जन, नकदी प्रवाह, बाजार हिस्सा, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को 'क्षति' के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सम्बद्ध देषों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही क्षति के पर्याप्त कारण हैं जो यह पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच की अवधि

10. वर्तमान जांच के उद्देष्यों के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 (12 माह) है। तथापि, क्षति का निर्धारण करने के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010, अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 से मार्च, 2012 और जांच की अवधि (पीओआई) के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

11 संबद्ध देषों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देषों की सरकारों को भारत स्थित उनके राज दूतावासों/आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के जिए, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय—सीमा के भीतर इस जांच से संगत प्रस्तुतिकरण कर सकता है और उसे निम्नलिखित पते पर प्रेषित कर सकता है:—

निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबद्ध षुल्क महानिदेषालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन नई दिल्ली—110107 समय— सीमा

- 12. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनिधक समय के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समयाविध के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
- 13. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनसार प्रदान कराई गई गोपनीय सूचना का पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार गोपनीय और अगोपनीय सार प्रदान कराएंगे। प्रष्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग—अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (षीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिन्हित (षीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

- किसी भी तरह के चिन्ह के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेत् स्वतंत्र होंगे। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रस्तुत सूचना के साथ इस बात का ठोस कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि वह सूचना प्रकट क्यों नही की जा सकती है और / अथवा उस सूचना का सारांष बनाना क्यों संभव नहीं है।
- अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हैं, सूचीबद्ध किया जाए अथवा रिक्त छोड़ दिया जाए संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांष गोपनीय आधार पर प्रस्तृत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विषेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्षा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया करना चाहिए।
- प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवष्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांष रूप से इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।
- सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवष्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विषिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे। सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
- नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। असहयोग
- यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवष्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिषें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES) INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2013

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol, originating in or exported from Australia, EU and Singapore.

No.14/01/2013-DGAD.-M/s Manali Petrochemicals Ltd., has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Australia, EU and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries).

And whereas, the Authority finds prima-facie that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & 'Standing'

2. The Application has been filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd on behalf of the domestic industry. As claimed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd, they are the sole producer of the subject goods in India and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol, a polymer, originating in or exported from the subject countries. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the "subject goods") from Australia, EU and Singapore. It is classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907.20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

4. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Countries involved

5. The countries/territory involved in the present investigation are Australia, Singapore and EU.

Normal Value

6. Normal Value for Australia, EU and Singapore: The applicant has constructed the normal value in respect of these subject countries stating that neither they were able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the subject countries nor the same are available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

7. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from EximNet BBS. Price adjustments have been allowed on account of Ocean freight, marine insurance, inland transportation, commission, port handling and port charges etc. to arrive at the

net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Dumping Margin

8. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows prima facie significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

9. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and decline in profitability, return on capital employed, cash flow, market share, production, capacity utilization etc. of the domestic industry. There is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

10. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January 2012 to 31st December 2012 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2009 to March2010, April 2010 to March 2011, April 2011 to March-2012 and the period of investigation (POI) has been considered.

Submission of information

11. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies/Economic and Cultural Centre in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107

Time limit

12. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

13. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-

Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

- 14. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
- 15. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
- 16. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 17. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 18. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

19. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

20. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J.S. DEEPAK, Designated Authority